

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 10 इलाहाबाद।

UPAD040290572022



परिवाद सं० 268/2022

सरिता

बनाम

मयंक आदि

25.07.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र डी०आई०जी० इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.04.2015 को मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराए जाने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में सम्बंधित थाने में विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत मु०अ०सं० 170/2015 अन्तर्गत धारा 323, 504, 498ए भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना शिवकुटी जनपद इलाहाबाद में अंतिम आख्या सं० 01/2016 न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दी गयी। जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत उक्त अंतिम आख्या को दिनांक 05.12.2019 को निरस्त करते हुए उक्त मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादिनी ने अपने परिवादपत्र में किए गए कथनों के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० एवं अपने कथन के समर्थन में धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अपने चाचा सिंहासन सिंह का बयान अंकित कराया है।

आवेदिका ने दिनांक 07.07.2015 को विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना शिवकुटी जनपद इलाहाबाद में पंजीकृत करायी थी। बाद विवेचना विपक्षीगण के विरुद्ध अंतिम आख्या सं० 01/2016 न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी जिस पर आवेदिका ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में स्वीकार किया गया। आवेदिका के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० व उक्त अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्षियों के बयान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका का पति व्यवसाय से डाक्टर है, जो महाराष्ट्र में निवास करता है जिसको एक पुत्र भी है। उभयपक्षों के बीच आपसी मतभेद को लेकर विवाद परिलक्षित होता है। पत्रावली पर विपक्षीगण को तलब किए जाने हेतु पर्याप्त आधार परिलक्षित नहीं होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को तलब किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी सरिता सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25.07.2020

(शैलेश कुमार मौर्य)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०10 इलाहाबाद।
जे०ओ० कोर्ड नं० 2290